

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF SHER SINGH) (a) and (b) For the Drought Prone Areas Programme (formerly called Rural Works Programme), an outlay upto Rs 2 crores would be available for each selected district during the Fourth Plan period. The State Governments have to draw up master plans for each selected district and based on these plans, individual works to be taken up in different sectors are to be sanctioned. Pending the finalisation of master plans for Sidhi district, schemes with an estimated cost of Rs 87.33 lakhs were sanctioned in the first year of the Programme itself on an *ad hoc* basis. Depending on the progress of expenditure, funds are also released to the State Government and the execution of works is not held up for want of funds.

Jobless Doctors

*97 SHRI BHOLA MANJHI Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state

(a) the number of doctors who are jobless

(b) whether the Indian Medical Association surveyed the position in different States regarding jobless doctors, and

(c) if so, their findings?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING & HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) (a) We have no statistical data showing the number of jobless doctors in the country. There is an overall shortage of doctors in the country particularly in rural areas,

(b) No

(c) Does not arise

सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना

*98. श्री राम रतन शर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डा० बी० पी० घाटे ने हाल ही में यह सुझाव दिया था कि देश में एक सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये, और

(ख) यदि हा, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्यमंत्री (प्रो० एस० नुबल हसन) (क) पूना विश्वविद्यालय के कुलपति ने रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है। रक्षा मंत्रालय ने, पूना विश्वविद्यालय तथा महाराष्ट्र सरकार से पूना क्षेत्र के सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सम्मिलित करने के लिये सहमति प्राप्त की थी। पूना विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह महसूस किया कि पूना स्थित संस्थानों को पूना विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया जाना चाहिये, न कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में। रक्षा सचिव से विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने व व्यक्त किया कि यदि रक्षा-सेवा-विश्वविद्यालय की स्थापना अलग से होती है, तो यह दूसरी बात है और तब पूना विश्वविद्यालय को इसमें कोई प्राप्ति नहीं होगी।

(ख) मामला रक्षा मंत्रालय के विचार-धीन है।